होगी और क्या सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(घ) इस क्षेत्र के बैंकों का क्या योगदान रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1981 की जनगणना आंकड़ों के योजन के आधार पर 1,3,2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा कुल आवास स्टाक 192.6 मिलियन होने का अनुमान लगाया है जिसमें आवास स्टाक 168.2 मिलियन स्वीकार्य होगा ।

(ख) आवास राज्य का विषय है । आवास की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त योजनाओं को प्रतिपादित करना मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । राष्ट्रीय आवास नीति में बहुत से उपाय निर्धारित हैं जिनको केंद्र/राज्य तथा नगर पालिका स्तर पर सरकार द्वारा करना होगा जिससे आवास निर्माण की गति में वृद्धि होगी । वे उपाय इस प्रकार हैं :

(i) कानूनी तथा अन्य प्रतिबन्ध हटाना ।

(ii) आवास वित्त के अंतर्वाह में वृद्धि करना ।

(iii) विकसित भूमि की आपूर्ति, मूलभूत सेवाओं, भवन सामग्रियों आदि में वृद्धि करना ।

(iv) केंद्र सरकार के मार्ग दर्शन में राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध कार्य योजनाओं का प्रतिपादन और कार्यान्वयन ।

(ग) सन 2001 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी 25.5 मिलियन एकक अनुमानित है । राज्य क्षेत्र आवास स्कीमों के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना नामक एक केंद्रीय स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुवा मजदूरों को मुफ्त आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रचालन में है । यह स्कीम कतिपय संशोधनों सहित 8वीं योजना में जारी रहेगी । 1991-92 तक इस स्कीम के अंतर्गत 10.57 लाख मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में आवास कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए ये बैंक प्रतिवर्ष अपनी संवृद्धि निक्षेपों का 1.5 प्रतिशत निर्धारित कर रहे हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में धपलेबाजी

1759. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 6 सितम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं/धांधली, षडयंत्र और धपलेबाजी के मामलों की जांच के संबंध में क्या प्रगति हुई है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने के लिए सौंपे गए थे ; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-कानूनी नियुक्तियों से संबंधित अपराधों की जांच के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । केंद्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

Floating of Irrigation Bond

1760. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to float an Irrigation Bond to raise adequate resources for agricultural during the Eighth Plan period; and